भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 189

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 6 दिसम्‍बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरकों की उपलब्‍धता और इसका उचित प्रयोग**

189. श्री हुसैन दलवई:

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश भर में गुणवत्‍तापूर्ण उर्वरकों की पर्याप्‍त उपलब्‍धता और इसके उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्‍यौरा क्‍या है;

(ख) क्‍या इन प्रयासों से छोटे और सीमान्‍त किसानों को अपनी फसलों की उत्‍पादकता बढ़ाने में मदद मिली है; यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ग) सरकार किस प्रकार एन, पी और के उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन को दूर करने का विचार रखती है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क):** प्रत्‍येक फसल मौसम अर्थात् खरीफ और रबी के शुरु होने से पहले कृषि एवं सहकारिता विभाग आगामी फसल मौसम के लिए उर्वरकों की मांग का आकलन करने हेतु अर्द्धवार्षिक आंच‍लिक सम्‍मेलन आयोजित करता है। सभी राज्‍यों के कृषि विभागों के अधिकारी, सभी उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधि, एफएआई के अधिकारी, रेल मंत्रालय और उर्वरक विभाग के अधिकारी इन अर्द्धवार्षिक आंचलिक सम्‍मेलनों में भाग लेते हैं।

सरकार ने देश में उर्वरकों की उपलब्‍धता सुनिश्‍चित करने के लिए निम्‍नलिखित कदम उठाए हैं:-

(क) कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) द्वारा राज्‍य सरकारों के परामर्श से प्रत्‍येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले मासिक आधार पर उर्वरक की मांग का आकलन एवं अनुमान लगाया जाता है।

-2-

(ख) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्‍तुत किये गये माह-वार और राज्‍य-वार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्‍यों को उर्वरकों की उचित/पर्याप्‍त मात्रा आबंटित करता है और निम्‍नलिखित प्रणाली के माध्‍यम से लगातार निगरानी रखता है:

(i) सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्‍त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली (www.urvarak.co.in) द्वारा, जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है, देश भर में की जा रही है।

(ii) राज्‍य सरकारों को अपने राज्‍य सांस्‍थानिक अभिकरणों, जैसे मार्कफेड इत्‍यादि के माध्‍यम से रेलवे रैक की यथा-समय मांग प्रस्‍तुत करके आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए उर्वरक उत्‍पादकों और आयातकर्ताओं के साथ समन्‍वय करने की भी नियमित रूप से सलाह दी जाती है।

(iii) कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), उर्वरक विभाग (डीओएफ), तथा रेल मंत्रालय द्वारा राज्‍य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्‍त रूप से नियमित साप्‍ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्‍य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरकों के प्रेषण में उपचारी कार्रवाई की जाती है।

(iv) उर्वरक की आवश्यकता और स्‍वदेशी उपलब्‍धता के बीच अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

**(ख):** जी हां, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्‍ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार खाद्यान्‍न उत्‍पादकता की पैदावार बढ़ रही है। ब्‍यौरा इस प्रकार है:-

|  |  |
| --- | --- |
| वर्ष | खाद्यान्‍नों की पैदावार(किग्रा./हेक्‍टेयर) |
| 2007-08 | 1860.0 |
| 2008-09 | 1908.8 |
| 2009-10 | 1797.6 |
| 2010-11 | 1930.0 |
| 2011-12 | 2079.0 |
| 2012-13 | 2125.0 |
| 2007-08 से 2012-13 तक वृद्धि - 14.25% | |

खाद्यान्‍न उत्‍पादकता के आंकड़े- खेत के आकार के अनुसार (छोटे और सीमांत किसानों जिनके पास 2 हेक्‍टेयर से कम भूमि है) नहीं रखे जाते हैं। तथापि, खाद्यान्‍नों की पैदावार में वृद्धि अन्‍य बातों के साथ-साथ सिंचाई स्थिति, फसल पद्धति, गुणवत्‍ता बीजों, उर्वरकों के साथ-साथ आदानों के अनुप्रयोग पर निर्भर करती है।

-3-

**(ग):** भारत सरकार द्वारा उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्‍नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(I) मृदा परीक्षण आधार पर कार्बनिक खादों के साथ-साथ उर्वरकों के संतुलित और युक्तिसंगत अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 2008-09 से **''राष्‍ट्रीय मृदा स्‍वास्‍थ्‍य एवं उर्वरण प्रबंधन परियोजना''** नामक एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मौजूदा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के साथ-साथ नई अचल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसटीएल) और नई चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्‍थापित करने का प्रावधान किया गया है। योजना के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

**(i) मृदा परीक्षण सेवा का सुदृढ़ बनाना:**

(क) अचल/चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएलएस) की स्‍थापना करना/मजबूत बनाना।(ख) उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण/क्षेत्र प्रदर्शनियां।(ग) डिजीटल जिला मृदा मानचित्र तैयार करना।

**(ii) एकीकृत पोषक-तत्‍व प्रबंधन के प्रयोग को बढ़ावा देना:**

मृदा स्‍वास्‍थ्‍य और उत्‍पादकता में सुधार करने और उसे बनाए रखने के लिए सरकार कार्बनिक खादों व जैव उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक एवं सूक्ष्‍म पोषक-तत्‍वों सहित रासायनिक उर्वरकों के तर्कसंगत प्रयोग के जरिए एकीकृत पोषक-तत्‍व प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है।

(II) भारतीय मृदा विज्ञान संस्‍थान (आईआईएसएस), भोपाल को 19 प्रमुख राज्‍यों (171 जिलों) में स्‍थल विशिष्‍ट सिफारिशें करने के लिए मृदा परीक्षण फसल प्रतिक्रिया (एसटीसीआर) डाटा सहित मृदा

उर्वरण स्थिति को परस्‍पर जोड़ने के साथ-साथ भू-संदर्भित मृदा उर्वरण मानचित्र तैयार करने की एक परियोजना की स्‍वीकृति भी दी गई है।

(III) **अनुकूलित उर्वरक**: स्‍थल विशिष्‍ट पोषक प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से मंत्रालय अनुकूलित उर्वरकों के प्रयोग को भी बढ़ावा दे रहा है ताकि अधिकतम उर्वरक प्रयोग दक्षता हासिल की जा सके। ये अनुकूलित उर्वरक बहु-पोषक तत्‍व वाहक हैं जिनमें बृहत और सूक्ष्‍म पोषक-तत्‍व शामिल होते हैं और इन्‍हें मृदा परीक्षण परिणामों के आधार पर मृदा एवं फसल के लिए विशिष्‍ट रूप से तैयार किया जाता है। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने एफसीओ, 1985 के तहत आज तक 25 ऐसे उर्वरकों को अधिसूचित किया है।

(IV) संपुष्‍ट उर्वरक: सूक्ष्‍म पोषक तत्‍वों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग संपुष्‍ट उर्वरकों के प्रयोग को भी प्रोत्‍साहन देता है जिनमें विभिन्‍न सूक्ष्‍म पोषक तत्‍व जैसे एनपीके के साथ-साथ जिंक, बोरोन आदि निहित होते हैं।

\*\*\*\*\*